(d) if so, what other measures Government propose to take to improve the standard of slum dwellers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The present policy of the Government emphasises an environmental improvement of urban slums in situ rather than their massive clearance and re-location. The State sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums is in operation in this regard. Under the Scheme, basic amenities like drinkign water supply, community baths and latrines, street lighting, paving of existing lanes and pathways etc. are provided in urban slums. Funds are provided in the State Annual Plans and the State Governments formulate and implement appropriate projects under the Scheme in accordance with their needs and priorities.

The World Bank assisted urban development projects in operation in Bombay, Calcutta, Madras and other cities have also substantial slum upgradation component. Considering the acute conditions in Bombay, the Government has also decided to provide special non-plan grant of Rs. 100 crores to the Government of Maharashtra during 7th Plan for tackling the acute problems of housing and slums in Bombay.

अनुसूचित जनजातियों को छूट

1384. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार भविष्य में इस श्रेणी के व्यक्तियों को कोई छूट प्रदान करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गौतमपुरी, दिल्ली में सड़कों का चौड़ा किया जाना

1385. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है, और किन-किन विशिष्ट स्थानों पर उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सड़कों को चौडा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां हो, तो उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गौतमपुरी में सड़कों को चौड़ा करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विधवाओं को रोजगार

1386. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधवाओं को रोजगार कार्यालयों में अपने नामों के पंजीयन की एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी नौकरियां नहीं दी जाती